



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 362] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जून 28, 1990/आसाढ़ 7, 1912  
No. 362] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1990/ASADHA 7, 1912

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

---

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1990

का. भा. 519(प्र):—बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) को, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है, धारा 48 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहाँ किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निवेशक बोर्ड का अधिकरण किया जाता है वहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार एक या अधिक प्रशासकों को सोसाइटी के कार्यकलापों

का एक वर्ष से अधिक की ऐसे अवधि के लिए जो अवधि केन्द्रीय रजिस्ट्रार के विवेक पर, समय समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु जिसकी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ;

श्रीर नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की बाबत प्रशासक को नियुक्ति के लिए दो वर्ष की उक्त अवधि 14 अक्टूबर, 1989 को समाप्त हो चुकी थी ;

श्रीर भारत सरकार के का. घा. सं. 796 (घ) तारीख 9 अक्टूबर, 1989 द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को बाबत अधिनियम की धारा 48 को उपधारा (1) के उपबंधों से छूट प्रदान करके प्रशासक को नियुक्ति की अवधि का विस्तार 30 जून, 1990 तक की और अवधि के लिए कर दिया गया था ;

श्रीर नागरिक पूर्ति विभाग ने जो नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग है 30 जून, 1990 के परे प्रशासक को बनाए रखने की, सिफारिश की है ;

श्रीर कृषि और सहकारिता मंत्र ने यह आवश्यक समझा है कि नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के निवेशक बोर्ड के निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 48 को उपधारा (1) के उपबंधों से छूट की अवधि का 30 जून, 1990 से परे 30 जुलाई, 1990 तक और विस्तार किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 48 को उपधारा (1) के उपबंधों से उस सीमा तक छूट देती है जिस तक प्रशासक, नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के कार्यकलापों का 30 जुलाई, 1990 तक की और अवधि के लिए प्रबंध करेगा ।

[सं. एल.—11011/11/89—एल. एण्ड एम.]

संगीता गंगोला, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1990

S.O. 519(E).—Whereas sub-section (1) of section 48 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) hereinafter referred to as the 'Act' provide that where the Board of Directors of a multi-State co-operativ.

society is superseded, the Central Registrar may appoint one or more administrators to manage the affairs of the society for such period not exceeding one year which period may, at the discretion of the Central Registrar, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period does not exceed two years;

And whereas the said period of two years for the appointment of an administrator in respect of National Co-operative Consumers Federation of India Limited, New Delhi expired on the 14th October, 1989;

And whereas the period of appointment of the administrator was extended for a further period upto 30th June, 1990 by granting an exemption from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act in respect of the National Co-operative Consumers Federation of India Limited as per S.O. No. 796(E) dated the 9th October, 1989 of the Government of India;

And whereas the Department of Civil Supplies, the administrative Department for the National Co-operative Consumers Federation of India Limited has recommended the continuance of the administrator beyond the 30th June, 1990;

And whereas the Department of Agriculture and Co-operation considered it necessary further to extend the period of exemption beyond 30th June, 1990 up to the 30th July, 1990 from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act for the purpose of holding election to the Board of Directors of the National Co-operative Consumers Federation of India Limited;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the Act, the Central Government hereby exempts the National Co-operative Consumers Federation of India Limited, New Delhi from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act to the extent that the administrator will manage the affairs of the National Co-operative Consumers Federation of India Limited for a further period upto 30th July, 1990.

[No. L-11011/11/89-L&M]

SANGITA GAIROLA, Dy. Secy.

